Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 11-05-2005

Participants : Singh Kunwar Rewati Raman

>

Title: Regarding need to provide small shops to unemployed youths by Urban Development Agencies throughout the country with a view to solving unemployment problem.

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : महोदय, बेरोजगारी इस देश में आजादी के बाद से ही एक उग्र समस्या रही है। रोजगार दिलाने के मामले में केन्द्रीय तथा अधिकांश राज्य सरकारों का रिकार्ड कुछ खास अच्छा नहीं है। चेन्नई जैसे शहर में बर्मा बाजार में वो पहले बिल्कुल छोटी दुकाने खोल कर किया गया प्रयास कुछ सराहनीय लगता है। अच्छा होता अगर केन्द्र राज्यों को कुछ सहायता देकर ऐसी छोटी दुकाने बना कर बेरोजगारों को मदद करता। यह करना तो दूर रहा बड़े तथा छोटे शहरों मे एक ओर नगर निगम खोंचे तथा पटरी पर काम धंध करने वालों का सामान उठा कर अपना कहर गिराने में कोइ कसर नहीं छोड़ते। दिल्ली में तो यह आम देखने में मिलता है। चाहे इण्डिया गेट और एनडीएमसी के इलाके हो या पुरानी दिल्ली के बाजार दूसरी ओर चाहे दरियागंज मण्डी के बाहर पटरी पर सब्जी या खोंचा लगाने वाले हो या यमुना पार के मधु विहार जैसे इलाके हो।

आजादी के 50 सालों से भी ऊपर बीत जाने के बाद आज तक केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कम से कम नगर निगमों के इन दस्तों को समाप्त तो कर दिया जाना चाहिए था। हाल ही में पुलिस पर निगरानी के कई कदमों की बात समाचार पत्रों में छपी है। मैं चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस इस तरह के अधिकारियों पर भी कैमरों के माध्यम से नजर रखे तथा अन्य शहर भी ऐसा करें।

साथ ही साथ दिल्ली की डीडीए हो या राज्यों के शहरी विकास बोर्ड, अच्छा हो यह संस्थान भी चेन्नई के बर्मा बाजार की तरह पटरी और खोंचे वालों के लिए बिल्कुल छोटी दुकाने खोल कर रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता करें।